



स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

इनसाइड ईरान के 400 किलो यूरेनियम पर 'अमेरिकी नजर'...>Pg12

2.5 करोड़ रुपए की किडनी 'डील'...>Pg03

मूल्य: ₹

कागजों पर चल रही थी कंपनी 37 करोड़ का जीएसटी घोटाला

फर्जी फर्म के जरिए ITC का दुरुपयोग, बिना कारोबार के ही पास कर दिया गया करोड़ों का टैक्स, संचालक पर FIR दर्ज

मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। शहर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) विभाग की सख्त निगरानी के बीच एक बड़े टैक्स चोरी घोटाले का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि 'सिंह इंटरप्राइजेज' नाम की एक फर्म के जरिए करीब 37.13 करोड़ रुपये के तस्कर घोटाले को अंजाम दिया गया। यह फर्म सिर्फ कागजों में संचालित हो रही थी और वास्तविक रूप से कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं पाई गई।

जीएसटी विभाग की टीम जब जांच के लिए मौके पर पहुंची, तो वहां केवल एक बंद गोदाम मिला। न कोई कर्मचारी, न कोई स्टॉक और न ही कारोबार का कोई प्रमाण—जिससे साफ हो गया कि पूरी फर्म महज फर्जी दस्तावेजों के सहारे खड़ी की गई थी। इसके बावजूद वर्ष 2024-25 के दौरान करोड़ों रुपये की खरीद-बिक्री कागजों में दर्शाई गई।

प्रारंभिक जांच के अनुसार, फर्म ने 36.74 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया और उसके आधार पर 37.13 करोड़ रुपये का टैक्स पास कर लिया। यह



पूरा खेल बिना किसी वास्तविक लेन-देन के अंजाम दिया गया, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा।

जांच अधिकारियों का कहना है कि यह घोटाला संगठित तरीके से अंजाम दिया गया है, जिसमें फर्जी बिलिंग और कागजी लेन-देन का सहारा लिया गया। विभाग को संदेह है कि इस नेटवर्क में अन्य फर्जी फर्मों भी शामिल हो सकती हैं, जिनके जरिए ITC का दुरुपयोग कर टैक्स चोरी की गई।

- 37.13 करोड़ रुपये के GST घोटाले का खुलासा
- फर्म केवल कागजों में संचालित मिली
- 36.74 करोड़ का फर्जी ITC वलेम
- कोई वास्तविक कारोबार या स्टॉक नहीं मिला
- फर्जी खरीद-बिक्री दिखाकर टैक्स पास
- संचालक के खिलाफ FIR दर्ज

मामले की गंभीरता को देखते हुए जीएसटी विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए फर्म संचालक अरविंद सिंह के खिलाफ गोविंद

ITC घोटाले का पैटर्न

फर्जी फर्म बनाकर कागजों में खरीद-बिक्री दिखाना और उसी आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लेना, GST धोखाधड़ी का सबसे आम तरीका बन चुका है। इस केस में भी बिना किसी वास्तविक लेन-देन के करोड़ों का ITC वलेम किया गया, जो सिस्टम की खामियों और निगरानी की चुनौती को उजागर करता है। फिलहाल, पुलिस और GST विभाग की संयुक्त जांच जारी है। माना जा रहा है कि यह मामला आगे और बड़े नेटवर्क का खुलासा कर सकता है, जिससे टैक्स चोरी के कई और राज सामने आ सकते हैं।

सरकार को कितना नुकसान?

37.13 करोड़ रुपये का टैक्स पास होना सीधे तौर पर सरकारी राजस्व की बड़ी क्षति है। ऐसे मामलों में केवल एक फर्म ही नहीं, बल्कि जुड़े नेटवर्क के जरिए नुकसान कई गुना बढ़ सकता है। यह पैसा विकास योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं पर असर डालता है।

जांच एजेंसियों की चुनौती

फर्जी कंपनियों अक्सर बंद गोदाम, फर्जी पते और नकली दस्तावेजों के जरिए बनाई जाती हैं। ऐसे में तस्कर विभाग को डिजिटल डेटा, बैंक ट्रान्जैक्शन और ई-वे बिल के सहारे जांच करनी पड़ती है। इस केस ने दिखाया कि टेक्नोलॉजी के बावजूद ऐसे नेटवर्क पकड़ना आसान नहीं है।

नगर थाने में FIR दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी

की तलाश के साथ-साथ पूरे नेटवर्क को खंगालने का काम शुरू कर दिया गया है।

यूपी में कालाबाजारी के खिलाफ कड़ा शिकंजा, 233 एफआईआर से हड़कंप

ईंधन माफिया पर सरकार का 'ऑपरेशन क्लीन'

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कालाबाजारी के खिलाफ सरकार ने ऐसा सख्त अभियान छेड़ा है, जिसने ईंधन माफियाओं की नींद उड़ा दी है। 12 मार्च से शुरू हुए इस व्यापक 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत अब तक प्रदेशभर में 19,882 निरीक्षण और छापेमारी की कार्रवाई की जा चुकी है। इस दौरान कालाबाजारी और अनियमितताओं के मामलों में कुल 233 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जो यह संकेत देती हैं कि अवैध ईंधन कारोबार कितनी गहराई तक फैला हुआ था।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इन 233 मामलों में 33 एफआईआर एलपीजी वितरकों के खिलाफ दर्ज की गई हैं, जबकि 200 एफआईआर सीधे तौर पर कालाबाजारी में लिप्त व्यक्तियों पर दर्ज हुई हैं। इस सख्त कार्रवाई के दौरान मौके से 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 237 व्यक्तियों को अभियोजित किया गया है। यह संख्या इस

19,882

छापों से खुला गोरखधंधा, 20 गिरफ्तार—लाखों किलोलीटर स्टॉक के बीच सख्त निगरानी

बात का प्रमाण है कि प्रशासन अब किसी भी स्तर पर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।

सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान कई स्थानों पर पेट्रोल-डीजल की अवैध जमाखोरी, मिलावट और ऊंचे दामों पर बिक्री जैसे गंभीर उल्लंघन सामने आए हैं। कई एलपीजी एजेंसियों पर भी उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम गैस देने और ब्लैक मार्केटिंग करने के आरोप पाए गए। कार्रवाई के दौरान कई लाइसेंस निलंबित किए गए और कुछ मामलों में रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

सरकार की इस सख्ती के पीछे एक बड़ा उद्देश्य आम जनता को राहत देना और ईंधन



की पारदर्शी आपूर्ति सुनिश्चित करना है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 97,000 किलोलीटर पेट्रोल और 1,26,000 किलोलीटर डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, जिससे यह साफ है कि आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद कालाबाजारी करने वालों ने कृत्रिम संकट पैदा कर मुनाफाखोरी की कोशिश की, जिसे अब प्रशासन ने निर्णायक तरीके से कुचलने का

संकेत दे दिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और जिन क्षेत्रों से शिकायतें मिलेंगी, वहां विशेष टीमों को तैनात कर औचक निरीक्षण किए जाएंगे। साथ ही आम जनता से भी अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की अनियमितता या ओवरचार्जिंग की सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा

- 12 मार्च से अब तक 19,882 निरीक्षण/छापे
- कुल 233 एफआईआर दर्ज
- 33 एफआईआर एलपीजी वितरकों पर, 200 कालाबाजारियों पर
- 20 आरोपी गिरफ्तार, 237 अभियोजित
- प्रदेश में 97,000 KL पेट्रोल और 1,26,000 KL डीजल स्टॉक उपलब्ध
- कई लाइसेंस निलंबन/रद्दकरण की कार्रवाई में
- कालाबाजारी रोकने के लिए अभियान जारी रहेगा

सके। सरकार का यह रुख साफ कर देता है कि अब ईंधन की कालाबाजारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत चल रही इस मुहिम ने यह संदेश दे दिया है कि नियमों से खिलवाड़ करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 को लेकर नगर निगम तैयार, अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश

जोन स्तर पर रिपोर्टिंग, बाजारों में जागरूकता अभियान और छोटे नालों से अतिक्रमण हटाने पर फोकस

» प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की तैयारियों को लेकर नगर निगम ने पूरी ताकत झोंक दी है। गुरुवार को नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त करने और शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए। बैठक में अपर नगर आयुक्त (द्वितीय), मुख्य अभियंता, महाप्रबंधक जलकल, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी समेत सभी जोनल अधिकारी, अभियंता और स्वच्छता अधिकारी मौजूद रहे। नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए जमीनी स्तर पर ठोस कार्यवाही जरूरी है।



स्वच्छ भारत मिशन के तहत कूड़ा उठान, स्रोत पर कचरा पृथक्करण और सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। सभी जोनों को

प्रगति रिपोर्ट, अनुपालन आख्या और जियोटैग फोटो के साथ नियमित रिपोर्टिंग करने को कहा गया है। साथ ही व्यापारिक क्षेत्रों, बाजारों और विद्यालयों को जोड़कर स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 दिन के भीतर रोस्टर तैयार करने

के निर्देश दिए गए।

नगर आयुक्त ने डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण और सेग्रिगेशन को लेकर विशेष अभियान चलाने पर जोर देते हुए कहा कि इसकी नियमित मॉनिटरिंग और फोटो शेयरिंग अनिवार्य की जाए।

अतिक्रमण पर सख्ती, 15 दिन में दिखेगा असर

शहर में जल निकासी बाधित करने वाले अतिक्रमण पर भी नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। एक मीटर से कम चौड़े नालों पर बने रैम्प और अवैध पार्किंग को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। कार्टवाइ का फोटो-वीडियो रिकॉर्ड तैयार कर संबंधित लोगों पर जुर्माना लगाने को कहा गया है। मोतीझील सहित मेट्रो स्टेशनों के आसपास अतिक्रमण हटाने को प्राथमिकता दी गई है, ताकि यातायात सुचारु रह सके। शहर के प्रवेश द्वार से टर्निंग प्वाइंट तक 1 किमी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इस्टबिन, मैनहोल और सड़कों पर भी फोकस

नगर आयुक्त ने मेट्रो स्टेशनों के आसपास दुकानों पर 2 इस्टबिन अनिवार्य करने, घाटों पर स्थायी इस्टबिन लगाने, मैनहोल ढके रखने और सड़कों के गड्ढों की मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही बिजली के लटकते तारों से यातायात प्रभावित न हो, इसकी भी नियमित निगरानी करने को कहा गया।

नगर निगम द्वारा अतिक्रमण की सूची संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई है और 15 दिन बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। नगर आयुक्त ने चेतावनी दी कि लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई तय है।

सर्गाफ लूट कांड के तीन आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, दो के पैर में लगी गोली

ग्वालटोली लूट के बाद फिर वारदात की फिराक में निकले थे बदमाश, हथियार व लूट का माल बरामद



एआई जेनेरेटेड प्रतीकात्मक फोटो

» प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर। शहर के ग्वालटोली इलाके में सर्गाफ से हुई लूट की वारदात के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए तीन शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। कर्नलगंज थाना पुलिस और बदमाशों के बीच हुई इस मुठभेड़ में दो आरोपियों के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरे को पुलिस ने दौड़ाकर दबोच

लिया। पुलिस के अनुसार, 1 अप्रैल की रात ग्वालटोली थाना क्षेत्र के लाल इमली चौराहे के पास सर्गाफ रामू केसरवानी से तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। सर्गाफ दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाते हुए लूट कर फरार हो गए थे। घटना के बाद हरकत में आई कर्नलगंज पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की।

लिया गया। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने सर्गाफ लूट की वारदात कबूल कर ली है। इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस और लूट का सामान भी बरामद किया गया है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है।

शराबी ई-रिक्शा चालक ने टक्कर मारी, युवक की मौत

तीन साल की बच्ची को लेकर जा रहा था पिता

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। नई सड़क इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 44 वर्षीय मोहम्मद नौशाद की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नौशाद अपनी तीन साल की मासूम बच्ची के साथ सड़क से गुजर रहे थे, तभी शराब के नशे में ई-रिक्शा चला रहे चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी तेज थी कि नौशाद उछलकर सड़क किनारे पड़े नगर निगम के पाइप से जा टकराए और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर खून फैल गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल नौशाद को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मोहम्मद नौशाद परेड इलाके में ठेला लगाकर अपने परिवार का



गुजारा करते थे। परिवार में उनकी तीन साल की बच्ची के अलावा अब कोई कमाने वाला नहीं बचा है, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी ई-रिक्शा चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।



2.5 करोड़ रुपए की किडनी 'डील'

विदेशी मरीजों के नाम पर फूलता फूलता अंगों का काला कारोबार

अफ्रीकी महिला के ट्रांसप्लांट ने खोली परतें, नोएडा से ऑपरेट हो रहा था नेटवर्क

गरीब डोनर बने शिकार और अस्पताल बने ऑपरेशन सेंटर

स्वराज इंडिया फालोअप

मुख्य संवाददाता

कानपुर। कानपुर में उजागर हुए अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, यह मामला अब एक बड़े इंटरनेशनल सिंडिकेट के रूप में सामने आ रहा है। साउथ अफ्रीका की महिला (अरेबिका-परिवर्तित नाम) के 2.5 करोड़ में हुए ट्रांसप्लांट ने इस नेटवर्क की गहराई और विस्तार को उजागर कर दिया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, यह कोई स्थानीय गिरोह नहीं बल्कि देश-विदेश तक फैला संगठित मेडिकल नेटवर्क है, जिसमें डॉक्टर, दलाल, एजेंट और अस्पतालों की भूमिका सामने आ रही है।

जांच में सामने आया है कि विदेशी मरीजों को भारत में सस्ता और त्वरित इलाज का झांसा देकर इस नेटवर्क से जोड़ा जाता था। अफ्रीकी महिला के मामले में भी उसे एक 'फुल पैकेज' ऑफर किया गया, जिसमें डोनर की व्यवस्था से लेकर ऑपरेशन और रिकवरी तक सब कुछ शामिल था। पुलिस के मुताबिक, इस पूरे ट्रांसप्लांट के लिए करीब 2.5 रुपए करोड़ की रकम ली गई। यह रकम अलग-अलग चैनलों

नोएडा कनेक्शन: डॉक्टर बना नेटवर्क का 'कमांड सेंटर'

जांच एजेंसियों के अनुसार, नोएडा का एक डॉक्टर इस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था। वही विदेशी क्लाइंट्स से संपर्क करता, डील तय करता और फिर अलग-अलग शहरों में ट्रांसप्लांट की व्यवस्था करता था। गिरोह की कार्यप्रणाली बेहद गोपनीय थी। डॉक्टरों को जरूरत के हिसाब से बुलाया जाता और अस्पतालों का चयन 'सुरक्षित' लोकेशन के आधार पर होता था। ऑपरेशन के बाद टीम तुरंत बिखर जाती थी। पूरे ऑपरेशन को इस तरह अंजाम दिया जाता था कि किसी एक व्यक्ति या स्थान पर पूरी जानकारी न रहे।

गरीबों की मजबूरी बना 'किडनी मार्केट'

इस रैकेट का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इसमें डोनर के रूप में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निशाना बनाया जाता था। बिहार के छात्र आयुष का मामला इसका उदाहरण है। उसे 9-10 लाख रुपये देने का वादा किया गया, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद मात्र 6 लाख रुपये ही दिए गए। जांच में यह भी सामने आया है कि कई मामलों में डोनर को ऑपरेशन के बाद पर्याप्त चिकित्सा सुविधा भी नहीं दी गई। यानी न सिर्फ उनका शोषण हुआ, बल्कि उनके स्वास्थ्य के साथ भी गंभीर खिलवाड़ किया गया।

के माध्यम से नेटवर्क के विभिन्न हिस्सों में बांटी जाती थी। इस केस ने यह स्पष्ट कर दिया

वया यह मामला पूरी सच्चाई तक पहुंचेगा

कानपुर का यह किडनी ट्रांसप्लांट मामला अब केवल एक अपराधिक घटना नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़े संगठित नेटवर्क का संकेत है, जिसकी जड़ें देश से बाहर तक फैली हो सकती हैं। अफ्रीकी महिला के केस ने इस पूरे खेल को उजागर कर दिया है, लेकिन असली चुनौती अब इस नेटवर्क के सभी आरोपियों तक पहुंचना और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकना है। जांच एजेंसियों की कार्यवाही पर अब सबकी नजर है। वया यह मामला पूरी सच्चाई तक पहुंचेगा या फिर कुछ गिरफ्तारियों के बाद थम जाएगा, यह आने वाला समय बताएगा।

है कि गिरोह विदेशी मरीजों को टारगेट कर मोटी कमाई कर रहा था।

मेडिकल टूरिज्म की आड़ में अवैध कारोबार

भारत में मेडिकल टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसी का फायदा उठाकर कुछ गिरोह अवैध ट्रांसप्लांट को अंजाम दे रहे हैं। विदेशी मरीजों को कम खर्च और जल्दी इलाज का लालच देकर कानून से बचने की कोशिश की जाती है।

निगरानी तंत्र की विफलता

इतना बड़ा नेटवर्क लंबे समय तक सक्रिय रहा, यह दर्शाता है कि निगरानी तंत्र में गंभीर खामियां हैं। अस्पतालों की जांच, ट्रांसप्लांट की अनुमति प्रक्रिया और मरीजों के रिकॉर्ड की निगरानी में लापरवाही सामने आती है।

सामाजिक-आर्थिक मजबूरी का दोहन

गरीबी, बेरोजगारी और कर्ज जैसे कारण लोगों को इस तरह के खतरनाक फैसले लेने के लिए मजबूर करते हैं। गिरोह इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें डोनर बनने के लिए तैयार करता है।

कानून बनाम क्रियान्वयन

देश में अंग प्रत्यारोपण को लेकर सख्त कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका पालन सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान और मिलीभगत के कारण ऐसे रैकेट पनपते हैं।



- 2.5 करोड़ रुपए की डील से इंटरनेशनल नेटवर्क का खुलासा
- विदेशी मरीजों को बनाते थे टारगेट
- कई राज्यों में फैला संगठित गिरोह
- गरीबों को डोनर बनाकर किया जाता था शोषण
- एक ट्रांसप्लांट में लाखों का मुनाफा
- जांच में और बड़े नाम सामने आने की संभावना



एक ट्रांसप्लांट, कई किरदार-मुनाफा करोड़ों में

पुलिस के अनुसार, एक ट्रांसप्लांट में मरीज से 50 से 60 लाख रुपये तक वसूले जाते थे, जबकि डोनर को इसका एक छोटा हिस्सा ही दिया जाता था। इस पूरे ऑपरेशन में कई स्तर पर लोग जुड़े होते थे। जिसमें एजेंट का काम डोनर और मरीज की तलाश करना होता था। डॉक्टर को ऑपरेशन व अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराना होता था। जबकि फाइनेंसर पैसों का लेन-देन करता था। इस तरह एक ही केस में लाखों का मुनाफा कई हिस्सों में बांटा जाता था।

छापेमारी की रात: दो ऑपरेशन की तैयारी, गैंग फरार

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जिस दिन छापेमारी हुई, उस दिन दो अलग-अलग ट्रांसप्लांट की तैयारी चल रही थी। लेकिन जैसे ही गिरोह को पुलिस की भनक लगी, सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई अस्पतालों में छापेमारी कर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब फरार आरोपियों की तलाश जारी है और नेटवर्क की अन्य कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।



कानपुर किडनी सिंडिकेट

पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा



डॉ. प्रीति आहुजा आहुजा हॉस्पिटल, संचालक



डॉ. सुरजीत आहुजा आहुजा हॉस्पिटल, संचालक



शिवम अग्रवाल उर्फ शिवम काड़ा दलाल



डॉ. राजेश कुमार मेड लाइफ हॉस्पिटल, संचालक



डॉ. नरेंद्र सिंह प्रिया हॉस्पिटल, संचालक



डॉ. राम प्रकाश मेड लाइफ हॉस्पिटल, संचालक

सुतरखाना में धर्मशाला को बनाया 'ओयो मॉडल' !

» हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुतरखाना में अवैध निर्माण का खेल बेखौफ

» प्रशासन मौन, केडीए की कार्रवाई पर उठे सवाल - एक ही व्यक्ति पर बार-बार आरोप

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। शहर में अवैध निर्माण पर सख्ती के दावों की पोल एक बार फिर खुल गई है। जोन-एक के थाना हरबंस मोहाल अंतर्गत सुतरखाना क्षेत्र में नियमों को टेंगा दिखाते हुए धर्मशाला को कथित रूप से 'ओयो मॉडल' होटल में तब्दील करने का खेल सामने आया है। जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठे हैं और अवैध निर्माणकर्ता बेखौफ होकर नियमों की धजियां उड़ा रहे हैं। ताजा मामला सुतरखाना तिराहे पर स्थित केतकी देवी धर्मशाला का है, जहां पुरानी इमारत को तोड़-मरोड़ कर बहुमंजिला व्यावसायिक बिल्डिंग का रूप दिया जा रहा है। नीचे कई दुकानें बना दी गई हैं। आरोप है कि निर्माण कई फीट आगे बढ़ाकर किया गया है, जिससे न सिर्फ नियमों का उल्लंघन हो रहा है बल्कि आसपास की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है।



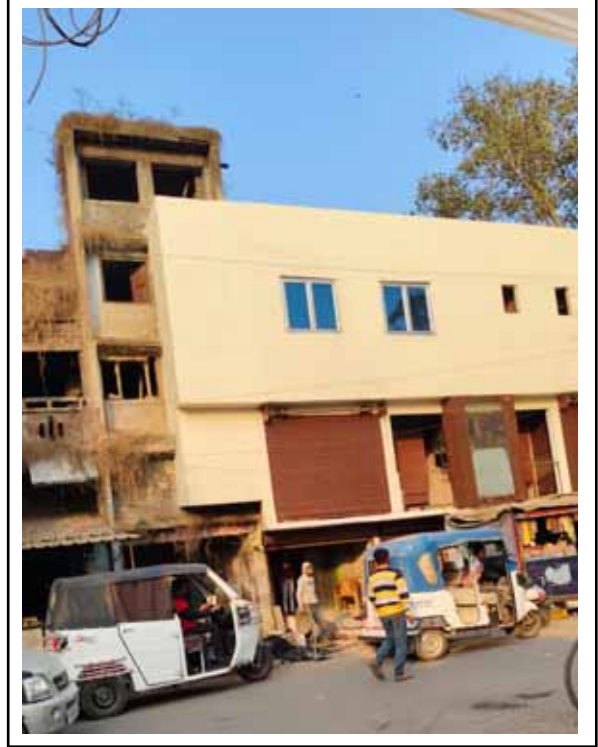
यह इमारत कभी धर्मशाला हुआ करती थी लेकिन माफियाओं ने इसको होटल में बदल दिया

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर 'स्वराज इंडिया' पहले भी प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद न तो निर्माण रुका और न ही कोई ठोस कार्रवाई हुई।

एक ही नाम, बार-बार विवाद

स्थानीय लोगों के अनुसार, इस अवैध निर्माण के पीछे आशु गुप्ता नामक व्यक्ति का हाथ है। आरोप

है कि यही व्यक्ति पहले भी क्षेत्र में विवादित निर्माण कर चुका है। बताया जाता है कि पिछले वर्ष इसी इलाके में एक मुस्लिम मजार को धरते हुए बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी गई थी। उस समय मामला इतना बढ़ा कि केडीए को कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग सील करनी पड़ी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में सील हटाकर दोबारा निर्माण शुरू कर दिया गया और पूरी इमारत खड़ी कर ली गई। अब उसी व्यक्ति द्वारा फिर से अवैध निर्माण किए जाने से क्षेत्र में



भारी आक्रोश है।

धर्मशाला या होटल? उठे गंभीर सवाल

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि धर्मशाला के नाम पर बनाई गई इस इमारत को अब होटल की तरह चलाने की तैयारी है, जहां कमरों का उपयोग किराए पर देने के लिए किया जाएगा। लोगों का कहना है कि यह पूरा मॉडल 'ओयो' की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, जो नियमों और लाइसेंसिंग प्रक्रिया का खुला उल्लंघन है।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि प्रशासन सख्ती दिखाए तो एक भी अवैध निर्माण खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन यहां लगातार हो रहे निर्माण यह साबित कर रहे हैं कि कहीं न कहीं जिम्मेदारों की अनदेखी या मिलीभगत जरूर है।

हादसे का खतरा, लोगों में डर

स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि बिना मानक और अनुमति के हो रहे इस निर्माण से भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। संकरी गलियों में खड़ी हो रही बहुमंजिला इमारतें आग या अन्य आपात स्थिति में जानलेवा साबित हो सकती हैं।

हनुमान जन्मोत्सव पर निःशुल्क संगीत कक्षा का शुभारंभ

भजनों से गुंजा रामेष्ट धाम, झूम उठे भक्त

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर रामेष्ट धाम, केशव मधुवन वाटिका (केशव नगर) में धार्मिक और सांस्कृतिक उल्लास का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर भगवान का विधिवत पूजन-अभिषेक किया गया तथा श्रद्धालुओं द्वारा सुंदरकांड का पाठ बड़े भाव और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। भजन-कीर्तन के दौरान पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा और श्रद्धालु झूमते नजर आए।

इसी शुभ अवसर पर भगवान रामेष्ट धाम की प्रेरणा से नगर के वरिष्ठ संगीतज्ञ विजय सिंह द्वारा निःशुल्क संगीत कक्षा का शुभारंभ किया गया। विजय सिंह राष्ट्रीय उत्कृष्ट संगीत शिक्षक सम्मान से सम्मानित हैं और विश्वप्रसिद्ध लेखक, गायक एवं संगीतकार स्वर्गीय रविन्द्र जैन के शिष्य रह चुके हैं।

समिति के महासचिव राजेन्द्र अवस्थी ने बताया कि विजय सिंह भारतीय संगीत के प्रचार-प्रसार के



लिए लगातार प्रयासरत हैं। वे भारतीय वाद्ययंत्र, गायन, लोकगीत, भजन और सुगम संगीत जैसी विधाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही बच्चों को मोबाइल से दूर कर संगीत की ओर प्रेरित करने का उनका प्रयास अत्यंत सराहनीय है।

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं ने संगीत सीखने

के लिए अपना पंजीकरण कराया।

इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष जयराम दुबे, श्याम बिहारी शर्मा, अशोक शुक्ला, नीरज शर्मा, आर.के. त्रिपाठी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, सी.बी. मिश्रा, बी.के. बाजपेई, राजेश्वरी दुबे, जया त्रिपाठी, पूनम कुमार, मोहनी बाजपेई सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कांग्रेस सोशल मीडिया कमेटी का गठन, कानपुर की निहारिका सिंह बनीं प्रदेश महासचिव

» किसान नेता चौधरी नरेंद्र सिंह की पौत्री, सक्रियता बढ़ने से सियासी गलियारों में चर्चा तेज

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया विभाग की नई कमेटी का गठन करते हुए प्रदेश स्तर पर पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया है। जारी सूची में कानपुर निवासी निहारिका सिंह को प्रदेश महासचिव (सोशल मीडिया) के महत्वपूर्ण पद पर जिम्मेदारी दी गई है।

निहारिका सिंह का नाम सामने आते ही राजनीतिक हलकों में उनकी सक्रियता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

खास बात यह है कि वह किसान नेता चौधरी नरेंद्र सिंह की पौत्री हैं, जिससे उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि को भी मजबूती मिलती है।



कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की इस नई सूची में प्रदेश महासचिव, सचिव और जिला/शहर अध्यक्षों के पदों पर कई नए चेहरों को मौका दिया गया है।

पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए संगठन को मजबूत करने और जनसंपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से यह नई टीम गठित की है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कांग्रेस संगठन इस मोर्चे पर नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है।

ऐसे में निहारिका सिंह को प्रदेश महासचिव बनाए जाने को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

सम्पादकीय

गिरावट रोकने को केंद्रीय बैंक बदले रणनीति

पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा संकट के बीच डॉलर के मुकाबले रुपये का अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुंचना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से मजबूत मुद्रा भंडार होने के बावजूद रुपये पर दबाव होना, देश के सामने कई तरह मुश्किलें पैदा कर सकता है। कहा जा रहा है कि भारत फिर 2013 जैसी स्थितियों से रूबरू है। लेकिन इस बार जहां मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है, वहीं तमाम वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति 2013 के मुकाबले मजबूत है। दरअसल, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच विदेशी निवेशक डॉलर को मजबूत निवेश के विकल्प के रूप में देखते हैं। इसीलिए वे उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी निकालकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश कर रहे हैं। जिससे डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपये जैसी दूसरी मुद्राएं कमजोर हो रही हैं। इसकी एक वजह अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती भी है। जिसका नकारात्मक प्रभाव भारत जैसे विकासशील देशों की मुद्राओं पर पड़ता है। यही वजह है कि एशिया में बेहद कमजोर स्थिति वाली मुद्राओं में रुपये भी शामिल है। ऐसी स्थिति में हमारे निर्यात सस्ते और आयात महंगे होने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। एक हकीकत यह भी है कि ईरान व अमेरिका के बीच जारी युद्ध से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने व पेट्रोलीयम पदार्थों की कीमतें बढ़ने से भी रुपये पर दबाव बढ़ा है। इसकी एक विसंगति यह भी है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का अधिकांश हिस्सा आयात करता है। जिसका प्रतिशत 85 फीसदी के करीब है। फलतः तेल कंपनियों अधिक डॉलर की मांग कर रही हैं, जिसका असर रुपये की सेहत पर भी पड़ रहा है। लेकिन पिछले एक साल में रुपये के मूल्य में दस फीसदी

गिरावट और डॉलर के मुकाबले उसका सर्वकालिक निम्न स्तर तक पहुंचना हमारी गंभीर चिंता का विषय होना ही चाहिए। आशंका जतायी जा रही है कि यदि ईरान व अमेरिका का युद्ध और लंबा खिंचता है तो रुपये के मूल्य में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि, अपनी तरफ से देश के केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक व रणनीतिक उपायों से रुपये की गिरावट को थमाने के प्रयास किए हैं, लेकिन उसका सीमित प्रभाव ही रहा है। भले ही भारत के पास सात सौ अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार हो, लेकिन उसका भी सीमित उपयोग ही रुपये के संरक्षण में हो सकता है। हालांकि, भारत के पास इतना विदेशी मुद्रा का भंडार है कि दस महीने के आयात को सहजता से संचालित किया जा सकता है। वास्तव में वैश्विक परिदृश्य में जारी उथल-पुथल से बाधित आर्थिकी और असुरक्षा के चलते डॉलर की बढ़ती मांग ने रुपये को कमजोर बनाया है। इसके बावजूद केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप से ही रुपये का गिरना संभल सकता है। केंद्रीय बैंक तेल कंपनियों के डॉलर के अतिरिक्त दबाव को कम करने को कदम उठा सकता है। एसबीआई की एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि तेल कंपनियों के लिये अलग डॉलर विंडो बनाये जाने से रुपये पर अचानक पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है। यही मांग बाजार में रुपये पर अतिरिक्त दबाव बना रही है। रिपोर्ट में एक सुझाव है कि इन कंपनियों के लिए अलग डॉलर विंडो बनाई जाए। अगर ऐसा होता है, तो बाजार में डॉलर की असली मांग और सप्लाई साफ दिखेगी। इससे रुपये पर अचानक पड़ने वाला दबाव कम भी हो सकता है। आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि रुपये को 'शाक एब्जॉर्बर' बनाकर हर दबाव को झेलने के लिये छोड़ देने की नीति पर पुनर्विचार की जरूरत है।

अंतरिक्ष अनुसंधान में अमेरिका को चीन की चुनौती

निरंजन मंडारी

चीन इस साल अपने नए मंगझोऊ (ड्रीम शिप) अंतरिक्ष यान की परीक्षण उड़ान आयोजित करने जा रहा है। यह अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र कक्षा में ले जाएगा। संभव है कि चंद्रमा पर अमेरिकी यात्री पहले उतर जाए, पर...चीन इस साल अपने नए मंगझोऊ (ड्रीम शिप) अंतरिक्ष यान की परीक्षण उड़ान आयोजित करने जा रहा है। यह अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र कक्षा में ले जाएगा। संभव है कि चंद्रमा पर अमेरिकी यात्री पहले उतर जाए, पर इस बात के आसार बन रहे हैं कि स्पेस साइंस में अब अमेरिका के साथ चीन बराबरी के स्तर पर आने की होड़ में है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नासा' इन दिनों अपने समानव चंद्र मिशन, आर्टेमिस-2 की तैयारी कर रही है, और अगले कुछ दिनों में किसी भी दिन इसका प्रक्षेपण हो जाएगा।



बेस बनाने का कार्यक्रम शुरू किया है। इसके विपरीत, नासा का आर्टेमिस चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम लगातार पिछड़ रहा है। आर्टेमिस-2 समानव फ्लाई-बाय यान है, लैंडिंग क्राफ्ट नहीं। कई बार स्थगित होने के बाद अप्रैल, 2026 में इसका प्रक्षेपण तय है। पहली अमेरिकी मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग को आर्टेमिस-4 तक टाल दिया गया है, जो 2028 से पहले संभव नहीं। चीन का कार्यक्रम, जो तीन दशकों से अधिक समय से एक एकीकृत योजना पर आधारित है, काफी हद तक उस राजनीतिक उथल-पुथल से अछूता रहा है, जो अमेरिका में चल रही है। चीन का समानव प्रोजेक्ट 921, सितंबर, 1992 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करना है। इस कार्यक्रम के तहत 2003 में चीनी अंतरिक्ष यात्री यांग लीवेई की पहली उड़ान के बाद से लगभग 15 मानवयुक्त मिशन संचालित किए जा चुके हैं। वर्ष 2011 में अमेरिका ने अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चीन को शामिल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद चीन ने अपना स्टेशन बनाने का फैसला किया और वह बना लिया। तियांगोंग, 2021 से काम कर रहा है और इसमें इस समय तीन चीनी अंतरिक्ष यात्री काम कर रहे हैं। चीन के किसी भी मानवयुक्त प्रक्षेपण में कोई मानवीय क्षति नहीं हुई है। चीन ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के दो सत्रों में विमानन और अंतरिक्ष उद्योग को 'स्तंभ उद्योग' का दर्जा दिया है। पहले यह विषय उभरते हुए क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत था। पहली बार, 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026-30) में स्पष्ट रूप से 2030 तक चीन को एक अंतरिक्ष शक्ति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पांच वर्षीय योजना में पुनरोपयोगी प्रक्षेपण यानों, बड़े पैमाने पर उपग्रह समूहों और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के व्यावसायीकरण को प्राथमिकता दी गई है।

इसमें चार यात्री जाएंगे, जो चंद्रमा का चक्कर लगाएंगे। उधर चीनी अंतरिक्ष एजेंसी (सीएनएसए) को उम्मीद है कि वह 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतार देगी। चीन पहले ही कई रोबोट चंद्रमा पर भेज चुका है और चंद्र नमूने वापस ला चुका है। चीन इस साल अपने नए मंगझोऊ (ड्रीम शिप) अंतरिक्ष यान की परीक्षण उड़ान आयोजित करने जा रहा है। यह अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र कक्षा में ले जाएगा। संभव है कि चंद्रमा पर अमेरिकी यात्री पहले उतर जाए, पर इस बात के आसार बन रहे हैं कि स्पेस साइंस में अब अमेरिका के साथ चीन बराबरी के स्तर पर आने की होड़ में है। अभी इसे बराबरी कहना आसान नहीं है, पर एक क्षेत्र ऐसा है, जिसमें वह अमेरिका के बराबर आ गया है या कुछ आगे निकल गया है। वह है स्पेस नेवीगेशन। चीन के 'बेइदू' ने अमेरिकी 'जीपीएस' को पीछे कर दिया है। इस बात को अमेरिकी विशेषज्ञ भी मानने लगे हैं। चीन को उम्मीद है कि वह 2035 तक चंद्रमा पर समानव वैज्ञानिक बेस का एक बुनियादी संस्करण तैयार कर लेगा, जिसे इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन (आईएलआरएस) कहा जाएगा। यह बेस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास बनाया जाएगा, जहां बर्फ के रूप में पानी मौजूद होने की संभावना है। इस परियोजना में रूस भी चीन के साथ है। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन ने लगभग 20 अरब डॉलर की लागत से चंद्रमा पर एक

बढ़ते कचरे का संकट भविष्य के लिए गंभीर खतरा

हमें अपने उपभोग के स्वरूप और जीवनशैली पर गंभीरता से पुनर्विचार की जरूरत है। भोगवादी आर्थिक मॉडल में निर्मित अधिकांश वस्तुएं अंततः कचरे में बदलती हैं। तेजी से बढ़ता कचरे का संकट निकट भविष्य में पर्यावरण, सेहत और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की ताजा रिपोर्टें संकेत करती हैं कि दुनिया तेजी से कचरे के ऐसे संकट की ओर बढ़ रही है, जो आने वाले दशकों में पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

वर्ष 2022 में दुनिया में लगभग 2.6 अरब टन कचरा उत्पन्न हुआ, जो 2050 तक बढ़कर 3.9 अरब टन तक पहुंचने की आशंका है। इसी क्रम में यूएनईपी की 'फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट' बताती है कि हर वर्ष लगभग 1 अरब टन भोजन बर्बाद होता है, जिसका लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा घरों से आता

है। यह स्थिति संसाधनों की भारी बर्बादी व समाज की उपभोग-प्रधान मानसिकता उजागर करती है। कचरे के बढ़ते ढेर केवल अस्वच्छता का प्रतीक नहीं, बल्कि वे पर्यावरण के लिए गंभीर वैज्ञानिक खतरा उत्पन्न करते हैं। विश्व बैंक की 'व्हाट अ वेस्ट' रिपोर्ट और यूएनईपी की 'ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक' रिपोर्ट स्पष्ट करती हैं कि लैंडफिल में जमे जैविक कचरे के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। यह ग्रीनहाउस गैस वैश्विक तापवृद्धि तेज करती है। इसके अलावा, कचरे के अनुचित निपटान से मिट्टी और भूजल प्रदूषित होते हैं, जिससे कृषि और मानव स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, खुले में कचरा जलाने से निकलने वाली विषैली गैसों और सूक्ष्म कण गंभीर बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। प्लास्टिक कचरे के विघटन से उत्पन्न सूक्ष्म कण जल स्रोतों में मिलकर खाद्य शृंखला का हिस्सा बन जाते हैं, जो मानव जीवन के लिए खतरा



बनते हैं। अहम प्रश्न है कि कचरे के ढेर आखिर किन कारणों से निरंतर बढ़ रहे हैं। इसका उत्तर हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति में निहित है, जो निरंतर अधिक से अधिक उपभोग करने के लिए प्रेरित करती है। समाजशास्त्री जिग्मुंट बॉमन के अनुसार, आधुनिक समाज एक 'उपभोक्ता समाज' में परिवर्तित हो चुका है, जहां वस्तुओं का निर्माण दीर्घकालिक

उपयोग के लिए नहीं, बल्कि शीघ्र त्याग के लिए किया जाता है। यूएनईपी की 'ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024' रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि वर्तमान 'उत्पादन-उपभोग-उत्पत्त्याग' आधारित अर्थव्यवस्था में निर्मित अधिकांश वस्तुएं अंततः कचरे में बदल जाती हैं। यदि यह मॉडल जारी रहा, तो कचरे की मात्रा और उससे जुड़े पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभाव लगातार बढ़ते जाएंगे। विश्व बैंक की 'व्हाट अ वेस्ट' रिपोर्ट यह संकेत देती है कि आर्थिक विकास, शहरीकरण और बढ़ते उपभोग के साथ कचरे की मात्रा में भी निरंतर वृद्धि होती है। इसी प्रकार, यूएनईपी रेखांकित करता है कि वर्तमान अस्थिर उपभोग और उत्पादन की प्रवृत्तियां कचरे के बढ़ते संकट का प्रमुख कारण हैं। 'ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक' रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि टिकाऊ समाधान के रूप में पुनः उपयोग, मरम्मत और पुनर्चक्रण जैसी प्रक्रियाओं को अपनाना आवश्यक है। जहां पारंपरिक

समाजों में वस्तुओं का उपयोग अधिक टिकाऊ और पुनः उपयोग पर आधारित था, वहीं आधुनिक उपभोग-प्रधान जीवनशैली ने इस संतुलन को समाप्त कर दिया। विश्व स्तर पर सीमित और सजग उपभोग को बढ़ावा देने के लिए कई संगठित प्रयास किए गए हैं। 'जीरो वेस्ट' आंदोलन, जिसे 21वीं सदी के प्रारंभ में संस्थागत रूप मिला, इस विचार को स्थापित करता है कि कचरे को न्यूनतम स्तर तक लाया जा सकता है। वहीं, वर्ष 2011 में ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ 'प्लास्टिक फ्री जुलाई' अभियान आज वैश्विक स्तर पर लोगों को सिंगल-यूज प्लास्टिक से दूरी बनाने को प्रेरित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 में 'इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे' की घोषणा दर्शाती है कि यह विषय अब वैश्विक प्राथमिकता है। इन आंदोलनों ने इस दिशा में जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई लेकिन केवल आंदोलनों के जरिये इस समस्या का पूर्ण समाधान संभव नहीं है।

नाइट ड्यूटी में लापरवाही पर फूटा गुस्सा

एसीपी का सख्त एक्शन, गायब पुलिसकर्मियों की बनेगी 'कुंडली'

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। कानपुर कमिश्नरेट के बिल्हौर सर्किल में बढ़ती चोरी और ट्रकों से डीजल चोरी की वारदातों के बीच नाइट ड्यूटी में लापरवाही पर पुलिस अफसरों का पारा चढ़ गया। देर रात हुए औचक निरीक्षण में कई पुलिसकर्मियों ड्यूटी से नदारद मिले, तो कुछ जगहों पर सतर्कता नाममात्र की दिखी। हालात देखकर एसीपी स्तर के अधिकारी ने सख्त नाराजगी जताते हुए साफ शब्दों में चेतावनी दी कि रात की ड्यूटी में ढिलाई अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी।

रात करीब 12 बजे एसीपी मंजय सिंह ने बिल्हौर क्षेत्र के संवेदनशील प्वाइंट्स का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान कई स्थानों पर पुलिसकर्मियों मुस्तैद जरूर मिले, लेकिन कई अहम जगहों पर ड्यूटी की हकीकत चौंकाने वाली रही। क्रॉस चेक के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों मौके से गायब मिले, जबकि कुछ गश्त में लापरवाही बरतते पाए गए। अचानक हुई इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

निरीक्षण के दौरान एसीपी ने मौके पर ही लापरवाह पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया और उनके खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए।

धूमधाम से दी गई सेवानिवृत्त शिक्षिका को विदाई

स्वराज इंडिया न्यूज

ककवन(बिल्हौर)। ककवन से बीते शैक्षिक। सत्र से एक मात्र शिक्षिका सरला देवी (प्र0अ0) का विदाई समारोह उच्च प्राथमिक विद्यालय अहमदपुर नदीहा में गुरुवार को बड़े धूम धाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय परिवार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक अहमदपुर नदीहा के शिक्षकों द्वारा विद्यालय परिसर में किया गया।

समारोह में ककवन विकास खण्ड व शिवराजपुर विकास खण्ड के शिक्षकों ने श्रीमती सरला देवी को उनके स्वर्णिम सेवा काल को पूरा करने व समाज में रहकर नवीन पारी की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर शीला गौतम, सुधा गुप्ता, जितेन्द्र राजपूत, शैलेन्द्र राजपूत, रूची पुरवार और नरेश ने विद्यालय में असेसमेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन

→ आधी रात औचक निरीक्षण में खुली पोल, टोल प्लाजा से लेकर गश्ती प्वाइंट तक मिली ढिलाई

सख्ती का क्या होगा असर ?

→ औचक निरीक्षण से पुलिसकर्मियों में जवाबदेही बढ़ेगी

→ संवेदनशील प्वाइंट्स पर निगरानी मजबूत होगी

→ अपराध नियंत्रण में तेजी आने की उम्मीद

उन्होंने दो ट्रक कहा कि नाइट ड्यूटी अपराध नियंत्रण की रीढ़ होती है, ऐसे में जरा सी लापरवाही भी बड़े अपराध को न्योता दे सकती है। क्षेत्र में लगातार हो रही डीजल चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए गश्त बढ़ाने, संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने और हर सूचना पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

एसीपी ने पुलिस रिस्पांस व्हीकल को भी हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र की निगरानी लगातार की जा



निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से जानकारी लेते एसीपी मंजय सिंह

रही है और ड्यूटी में कोताही बरतने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ किया कि आने वाले दिनों में ऐसे औचक निरीक्षण और तेज किए जाएंगे।

इसी क्रम में शिवराजपुर स्थित नेवादा टोल प्लाजा का भी निरीक्षण किया गया। यहां टोल परिसर में अनावश्यक रूप से खड़े वाहनों पर एसीपी ने कड़ी आपत्ति जताई। टोल

प्रबंधक को सख्त चेतावनी देते हुए कहा गया कि यदि परिसर में ट्रक या कंटेनर खड़े मिले तो सीधे जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही टोल कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें।

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि टोल प्लाजा और सुनसान मार्ग डीजल चोरी और

नाइट ड्यूटी में ढिलाई क्यों खतरनाक ?

- रात के समय पुलिस की सक्रियता ही अपराध रोकने का सबसे बड़ा जरिया
- गश्त कमजोर होते ही चोरी, लूट और डीजल चोरी जैसी घटनाएं बढ़ती हैं
- छोटी लापरवाही बड़े अपराध में बदल सकती है

डीजल चोरी: संगठित गिरोहों का खेल

- हाईवे और टोल प्लाजा के आसपास सक्रिय रहते हैं गिरोह
- खड़े ट्रकों को निशाना बनाकर मिन्टों में वारदात
- पुलिस की ढिलाई से अपराधियों के हौसले बुलंद

अन्य अपराधिक गतिविधियों के लिए संवेदनशील होते हैं। ऐसे में यहां ढिलाई सीधे अपराधियों को मौका देती है। यही वजह है कि अब इन स्थानों को विशेष निगरानी में लिया गया है।

रौगांव गांव में गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद युवक पर चाकू से हमला

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। अरौल थाना क्षेत्र के रौगांव गांव में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सड़क पर खड़े होने को लेकर शुरू हुई कहासुनी के बाद एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे वह घायल हो गया।

रौगांव निवासी आदित्य कुमार के अनुसार, वह गुरुवार शाम घर के बाहर खड़े थे। तभी गांव के ही अमित उर्फ छोटू यादव कार से वहां पहुंचे और सड़क पर खड़े होने को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। आरोप है कि छोटू यादव अपने भाई देवेश, रोहित और एक अन्य युवक के साथ कार से

→ कार सवार चार युवकों पर आरोप, विरोध करने पर मारपीट के बाद किया हमला

उतरकर आदित्य के साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान भीड़ जुटती देख आरोपी भागने लगे, लेकिन जाते-जाते चाकू से हमला कर दिया, जिससे आदित्य के हाथ में गंभीर चोट आई। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

रंजिश में युवक पर धारदार हथियार से वार: शिवराजपुर/बिल्हौर(कानपुर)। क्षेत्र के वार्ड चार मकखन सिंह नगर में आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर धारदार

हथियार से हमला कर दिया गया। हमले में घायल युवक को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पीयूष सिंह ने पुलिस को बताया कि वह मंगलवार रात खरेश्वर मार्ग स्थित ईट भट्टे की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में कुछ युवकों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि तुलापुरवा निवासी कुलदीप यादव, काकूपुर निहाल गांव के पुष्पेंद्र यादव और मदनपुर के आशू यादव ने गाली-गलौज करते हुए उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में पीयूष के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं। थाना प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

हनुमान जयंती पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धा की भीड़

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। गुरुवार को हनुमान जयंती पर चौबेपुर, शिवराजपुर, ककवन बिल्हौर और अरौल सहित आसपास के गांवों और कस्बों के हनुमान मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने विधिविधान से पूजा-अर्चना कर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया।

क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में दिनभर भंडारे और प्रसाद वितरण का आयोजन चलता रहा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग

→ क्षेत्र में भंडारे, कीर्तन व जागरण, हजारों श्रद्धालुओं ने किया पूजन-अर्चना



लिया। जय श्रीराम और बजरंगबली के जयकारों से पूरा वातावरण गूंजता रहा। अरौल के भीटीहवेली स्थित आगरा-लखनऊ

एक्सप्रेसवे के निकट बालाजी मंदिर पर भजन-कीर्तन व जागरण किया गया। जिसमें क्षेत्र के कई गांवों से हजारों श्रद्धालु पहुंचे।

ट्रांसफार्मर से तेल चोरी का प्रयास ग्रामीणों के पहुंचते ही भागे चोर

स्वराज इंडिया ब्यूरो

शिवराजपुर/बिल्हौर (कानपुर)। क्षेत्र के बैरी गांव में चोरों ने विद्युत ट्रांसफार्मर को निशाना बनाते हुए तेल और कीमती पुर्जे चोरी करने का प्रयास किया। रात में पहुंचे चोरों ने चालू लाइन के तार काटकर ट्रांसफार्मर को खोल लिया और अंदर से तेल निकालने लगे।

इसी दौरान गांव के लोगों को संदिग्ध गतिविधि की भनक लग गई। शोर सुनते ही ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े, जिसे देख चोर घबराकर भाग निकले। इस बीच चोर ट्रांसफार्मर से मामूली तेल ही निकाल सके, जबकि काफी मात्रा में तेल जमीन पर बह गया। सुबह जानकारी मिलने पर विद्युत विभाग

→ चालू लाइन के तार काटकर खोल दिया ट्रांसफार्मर
→ सूचना पर पहुंची टीम ने मरम्मत कर बहाल की बिजली

की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का निरीक्षण किया। विभागीय अधिकारियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दोपहर तक विभाग की टीम ने ट्रांसफार्मर में नया तेल भरकर मरम्मत का कार्य पूरा किया और क्षेत्र की बिजली आपूर्ति सुचारु कर दी। घटना के बाद ग्रामीणों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता व्याप्त है।

भक्त कलश यात्रा के साथ पंडोखर सरकार धाम में वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ

» विशेष संवाददाता/ स्वराज इंडिया

पंडोखर (मध्यप्रदेश)। पंडोखर सरकार धाम में आयोजित वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ भक्त कलश यात्रा के साथ श्रद्धा और आस्था के वातावरण में हुआ। इस अवसर पर देशभर से आए साधु-संतों एवं हजारों भक्तों की सहभागिता से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। कलश यात्रा पुष्पावती गंगा मैया के पावन घाट से प्रारंभ होकर पंडोखर धाम के विभिन्न मंदिरों एवं ग्राम क्षेत्र से होती हुई पुनः धाम परिसर पहुंची, जहां विधि-विधान के साथ यात्रा का समापन किया गया। यात्रा के दौरान भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा और हर ओर जयकारों की गूंज सुनाई दी।

यात्रा के उपरांत भक्त भागवत कथा का शुभारंभ किया गया, जिसके साथ ही वार्षिक महोत्सव का विधिवत आगाज हुआ। धाम के पीठाधीश्वर गुरु शरण जी महाराज ने कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान करते हुए देशभर से आए साधु-संतों का सम्मान किया।

इस दौरान पुष्पावती गंगा घाट पर भक्त गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्तों ने श्रद्धा भाव से

देशभर से आए साधु-संतों की उपस्थिति, पुष्पावती गंगा घाट पर गूंजे जयकारे



आरती में सहभागिता कर अपने आप को धन्य महसूस किया। महोत्सव में लगे मेले में बच्चों ने झूले और अन्य आकर्षणों का भरपूर आनंद लिया, जिससे आयोजन में उत्साह और उल्लास का माहौल बना रहा।

पीठाधीश्वर गुरु शरण जी महाराज ने देशभर के भक्तों को पंडोखर धाम आकर भागवत कथा श्रवण करने और वार्षिक महोत्सव

में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया। उन्होंने मेले में सेवा कर रहे कार्यसेवकों का उत्साहवर्धन करते हुए आयोजन को सफल बनाने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया।

पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धा, भक्ति और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने पंडोखर धाम को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया।



सम्मान और संवेदना के बीच विदा हुए दो गुरुजन, यादगार बना समारोह

आरपीएस इंटर कॉलेज में शिशुपाल सिंह पाल व राजकुमार श्रीवास्तव को भावभीनी विदाई



» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रसूलाबाद स्थित आरपीएस इंटर कॉलेज में 31 मार्च 2026 को अपना सेवाकाल पूर्ण करने वाले वरिष्ठ शिक्षक शिशुपाल सिंह पाल एवं राजकुमार श्रीवास्तव के सम्मान में भक्त विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार ने दोनों शिक्षकों के दीर्घकालीन योगदान को याद करते हुए उन्हें

भावभीनी विदाई दी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य डीपी शुक्ला ने कहा कि दोनों शिक्षकों ने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कीं और विद्यालय में अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका अनुभव, ज्ञान और मार्गदर्शन समाज व विद्यालय परिवार के लिए अमूल्य धरोहर रहेगा।

समारोह के दौरान व्यायाम शिक्षक जितेंद्र त्रिपाठी 'जीतू' ने दोनों शिक्षकों के स्वस्थ, सुखद एवं सक्रिय जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में ऐसे अनुभवी शिक्षकों की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रहती है। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों ने अंगवस्त्र, उपहार एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर दोनों शिक्षकों को सम्मानित किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान भावनात्मक माहौल बना रहा और उपस्थित लोग उनके साथ बिताए गए पलों को याद कर भावुक नजर आए। समारोह में उपप्रधानाचार्य अजय पाल यादव, बंगाली बाबू शुक्ला, दुर्गेश त्रिपाठी, विनीत कुमार, शर्मा जी प्रजापति, बृजेंद्र सविता, अवधेश पाल, संदीप गुप्ता, भानु प्रताप, सुरेश सिंह, रामगोपाल बाथम, अवधेश दीक्षित सहित अनेक शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

सदिग्ध हालात में कंटेनर चालक की मौत परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

» शव पेड़ से लटका मिला, पैसे और दस्तावेज गायब, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया मार्ग जाम

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। शिवली थाना क्षेत्र में एक कंटेनर चालक की सदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक का शव पेड़ से गमछे के सहारे लटका मिला, जिसके बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने कल्याणपुर-शिवली मार्ग जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। काफी मशकत के बाद पुलिस ने लोगों को शांत कर जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

जानकारी के अनुसार बाघपुर निवासी रंजीत (पुत्र मौजी लाल) कंटेनर चालक था और वाहन को लोडिंग के लिए ले जा रहा था। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले कंटेनर बैंक करते समय उसकी एक कार से मामूली टक्कर हो गई थी, जिसको लेकर कहासुनी भी हुई थी। इसके अगले दिन उसका शव पेड़ से लटका मिला।

घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों के अनुसार जब शव मिला तो युवक के पैर जमीन को छू रहे थे और उसके शरीर के ऊपरी हिस्से में कपड़े नहीं



थे, जबकि उसने पैट पहन रखी थी। मृतक के पास मौजूद करीब 55 हजार रुपये, ड्राइविंग लाइसेंस और एटीएम कार्ड भी गायब बताए जा रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर सड़क जाम कर दी, जिससे यातायात बाधित रहा। सूचना पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार ने समझा-बुझाकर लोगों को शांत कराया। कोतवाल अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मामले में तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जाएगी। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच में जुट गई है।

खेत में मिला युवक का खून से सना शव, हत्या की आशंका

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, मोबाइल गायब मिलने से बढ़ी शंका

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। क्षेत्र में गुरुवार शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक 19 वर्षीय युवक की हत्या कर उसका शव गेहूं के खेत में फेंक दिया गया। शव खून से लथपथ हालत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जुट गई।



मृतक की फाइल फोटो



दौरान रामगंगा नहर पटरी मार्ग पर खखरा पुल के पास मकरंदपुर बंधा गांव की ओर जाने वाले रास्ते के किनारे गेहूं के खेत में उसका शव खून से सना हुआ पड़ा मिला। राहगीरों की नजर पड़ते ही उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पास खड़ी बाइक के नंबर के आधार पर मृतक की पहचान कर परिजनों को सूचना दी।

घटना की खबर मिलते ही परिजन

मौके पर पहुंच गए। मृतक के पिता रामलखन ने बताया कि राजा बाबू के मोबाइल पर रास्ते में बार-बार किसी का फोन आ रहा था, जिसके बाद यह घटना हुई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडेय, सीओ रसूलाबाद सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण

कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान मृतक का मोबाइल फोन मौके से गायब मिला, जिससे हत्या की आशंका और गहरी गई है। कोतवाली अम्मरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही घटना का खुलासा करने का दावा किया है।

यमुना नदी में मिला अज्ञात महिला का शव पुलिस जांच में जुटी

» सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत यमुना नदी में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, यमुना नदी में मछुआरों द्वारा लगाए गए मछली पकड़ने के जाल में एक महिला का शव फंसा हुआ मिला। मछुआरों ने तुरंत इसकी सूचना भोगनीपुर कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके

पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की। अमरौधा चौकी इंचार्ज अमित कुमार पोरवाल के अनुसार, मृतक की उम्र लगभग 45 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। महिला बुर्का पहने हुए थी, लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार का कोई पहचान पत्र नहीं मिला, जिससे उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस द्वारा महिला का फोटो जनपद के सभी संबंधित थानों में भेज दिया गया है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल, पुलिस महिला की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।

गंगा पुल पर ट्रैक कार्य का असर

13 अप्रैल तक झांसी इंटरसिटी गोविंदपुरी तक चलेगी

3 से 13 अप्रैल तक बदला रूट, यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था की सलाह

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। झांसी से लखनऊ के बीच यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। कानपुर स्थित गंगा रेल पुल पर चल रहे ट्रैक बदलने के कार्य के कारण इस रूट की प्रमुख ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। रेलवे प्रशासन ने पहले इन ट्रेनों को पूरी तरह निरस्त कर दिया था, लेकिन अब यात्रियों को आंशिक राहत देते हुए संशोधित रूट पर संचालन शुरू कर दिया गया है।

पुखरायां रेलवे स्टेशन के अधीक्षक वी.के. प्रजापति के अनुसार, झांसी-लखनऊ के बीच संचालित होने वाली 11109 झांसी-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक केवल झांसी से गोविंदपुरी स्टेशन तक ही चलाई जाएगी। इस



अवधि में ट्रेन लखनऊ तक नहीं जाएगी, जिससे यात्रियों को गोविंदपुरी स्टेशन पर उतरकर आगे की यात्रा के लिए अन्य साधनों का सहारा लेना होगा।

वहीं वापसी दिशा में 11110 इंटरसिटी एक्सप्रेस भी प्रभावित रहेगी।

यह ट्रेन 3 अप्रैल से 13 मई तक गोविंदपुरी से झांसी के बीच ही संचालित की जाएगी। यानी

लखनऊ से सीधे झांसी जाने वाले यात्रियों को भी इस बदलाव का असर झेलना पड़ेगा। इसके अलावा झांसी-लखनऊ के बीच चलने वाली 64701 पैसेंजर ट्रेन के संचालन में भी बदलाव किया गया है। यह ट्रेन 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक झांसी से गोविंदपुरी होते हुए केवल फतेहपुर तक ही चलाई जाएगी। इससे दैनिक यात्रियों और स्थानीय सफर करने

वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, कानपुर में गंगा पुल पर रेल पटरी बदलने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह कार्य सुरक्षा और बेहतर रेल संचालन के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है। कार्य पूरा होने तक ट्रेनों का संचालन सीमित रूट पर ही किया जाएगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। साथ ही गोविंदपुरी या फतेहपुर से आगे की यात्रा के लिए बस, टैक्सी या अन्य वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

संदिग्ध हालात में फांसी लगाकर की आत्महत्या

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के परेहरापुर गांव में एक व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से गांव में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया। परेहरापुर निवासी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि उसके बड़े भाई जितेंद्र कुमार (48) ने घर के अंदर पंखे के कुंडे से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची भोगनीपुर कोतवाली पुलिस व पुखरायां चौकी इंचार्ज अम्मरेंद्र प्रताप सिंह ने मौके पर जांच-पड़ताल कर आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है।

रसूलाबाद: गृह कलह से तंग आकर बुजुर्ग ने दी जान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रसूलाबाद क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। असालतगंज ग्राम पंचायत का मजरा कंधिया निवासी लाल जीत उर्फ प्रहलाद ने घर से दूर अपने खेत में गमछे के सहारे फांसी लगाकर



आत्महत्या कर ली। कहा जा रहा है कि युवक ने गृह कलह के चलते यह कदम उठाया। वहीं पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

नौबस्ता-हमीरपुर हाईवे को मिलेगी रफ्तार 6.49 करोड़ की फोरलेन परियोजना मंजूर

सांसद रमेश अवस्थी की पहल से जाम से मिलेगी राहत, 5 किमी दायरे में होगा निर्माण

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। शहर की सबसे बड़ी यातायात समस्याओं में शुमार नौबस्ता-हमीरपुर हाईवे पर अब राहत की उम्मीद जगी है। कानपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमेश अवस्थी के प्रयासों से इस मार्ग को फोरलेन बनाने की परियोजना को मंजूरी मिल गई है। करीब 6.49 करोड़ रुपये की लागत से नौबस्ता चौराहे से लगभग 5 किमी तक सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे लाखों लोगों को जाम से राहत मिलेगी।



बताया गया कि इस मार्ग पर लंबे समय से भारी वाहनों के दबाव और जर्जर सड़क के कारण यातायात व्यवस्था चरमराई हुई थी।

सांसद ने 1 जनवरी 2025 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया था और फोरलेन निर्माण का प्रस्ताव रखा था।

इस पहल का संज्ञान लेते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने परियोजना को स्वीकृति दे दी है। एनएचएआई के परियोजना निदेशक (कानपुर इकाई) के अनुसार 18 मार्च 2026 को निविदा अवार्ड की जा चुकी है और रियायत अनुबंध की प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

फोरलेन निर्माण से बिनगावां, यशोदानगर, पशुपतिनगर, हंसपुरम, आवास विकास, किदवई नगर और बसंत विहार समेत आसपास के कई इलाकों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। योजना लगने वाले जाम से



निजात मिलेगी और दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है।

इस उपलब्धि पर सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि क्षेत्र का समग्र विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताते हुए कहा कि इस परियोजना से कानपुर की यातायात व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह परियोजना जल्द ही धरातल पर दिखाई देगी।

ईएमटी डे पर एंबुलेंस कर्मियों का सम्मान

» सेवा और समर्पण को मिला सलाम

» केक काटकर मनाई खुशी, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिला सम्मान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। 108 व 102 एंबुलेंस सेवा के ईएमटी डे पर आयोजित कार्यक्रम में सेवा, समर्पण और टीमवर्क की प्रेरणादायक झलक देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान एंबुलेंस कर्मियों ने एक-दूसरे को

मिठाई खिलाकर और केक काटकर खुशी जाहिर की। पूरे आयोजन में आपसी सहयोग और कर्तव्यनिष्ठा का भाव स्पष्ट रूप से नजर आया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ए. के. सिंह ने एंबुलेंस कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि ईएमटी और पायलट आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि



दुर्घटनाओं और गंभीर हालात में ये कर्मी बिना देर किए मौके पर पहुंचकर मरीजों की जान देने का संकल्प लिया।

बचाते हैं, जो अत्यंत सराहनीय है।

कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सीएमओ ने कहा कि यह सम्मान अन्य कर्मियों को भी बेहतर सेवा देने के लिए प्रेरित करेगा। इस मौके पर प्रोग्राम मैनेजर, जिला प्रभारी अभिषेक तिवारी और मोहम्मद ताहा अंसारी सहित ईएमटी व पायलट स्टाफ मौजूद रहा। अंत में सभी ने बेहतर और संवेदनशील सेवा

बॉम्बे हॉस्पिटल

24 घण्टे इमरजेन्सी सुविधाएं

नियर आघू रोड, कानपुर-आगरा हाईवे, अकबरपुर, कानपुर देहात

नया पुराना फेक्चर, जोड़ों का दर्द, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, हाथ-पैर का टेढ़ापन, इत्यादि बीमारियों हेतु परामर्श समस्त प्रकार के हड्डी के आपरेशनकी सुविधा।

हड्डी के समस्त ऑपरेशन सी-आर्म मशीन द्वारा

डॉ. स्वाती बाजपेयी
MBBS, MD
टी.बी. एवं चेस्ट रोग
समय प्रतिदिन 4 से 6 बजे

डॉ. जितेन्द्र कटियार
फिजीयन एज्ड सर्जन (सिजेसी)
खरब घेराव, हाथ, बगदावुड, फेफ व लीवर रोग, टी.बी. रोग, कर्करोग, अस्वस्थ

डॉ. जे.पी. पाल
MBBS, MD, (Medicine)
CCDM, (London)
शरीरियर कान्सल्टेंट फिजीयन सर्जन
खरब घेराव, हाथ, बगदावुड, फेफ व लीवर रोग

डॉ. जे. दास
MBBS, DCH
बच्चों के डॉक्टर

डॉ. सन्तोष गुप्ता
MBBS, MS
जनरल सर्जन

डा० सुरेश यादव
डायरेक्टर

मो. : 9820470599, 8355017999, 8858997333

आजादी के 79 साल बाद भी 'गुलामी'

सतहरिया में ब्रिटिश दौर का लीज कानून बना उद्योग का गला घोटने वाला फंदा

मालिकाना हक से वंचित उद्यमी, हर बदलाव के लिए अनुमति और रिश्वत का आरोप, फ्रीहोल्ड की मांग तेज

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

जौनपुर। देश आजादी का अमृतकाल मना रहा है, लेकिन जौनपुर के सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र में आज भी अंग्रेजों के जमाने का कानून उद्योगों की रफतार पर ब्रेक लगाए खड़ा है। यहां लागू भूमि 'लीज होल्ड' व्यवस्था उद्यमियों के लिए किसी काले कानून से कम नहीं रह गई है। आजादी के करीब आठ दशक बाद भी मालिकाना हक न मिल पाने की टीस अब खुलकर विरोध में बदल रही है।

सतहरिया के उद्यमियों का कहना है कि ब्रिटिश काल में बनाई गई यह व्यवस्था आज के प्रतिस्पर्धी औद्योगिक माहौल में पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुकी है। इसके

चलते न केवल उद्योगों का विस्तार बाधित हो रहा है, बल्कि निवेश और नवाचार पर भी सीधा असर पड़ रहा है। उद्यमियों का आरोप है कि छोटे-छोटे बदलाव जैसे नया उत्पाद शुरू करना, उत्पादन सीमा में संशोधन, यूनिट का हस्तांतरण या किराये पर देना भी बिना सरकारी अनुमति के संभव नहीं है।

इस प्रक्रिया में उन्हें बार-बार सीडा और उद्योग विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं। कई उद्यमियों ने यह भी आरोप लगाया कि अनुमति प्रक्रिया के नाम पर भ्रष्टाचार पनप रहा है, जिससे उद्योग चलाना और कठिन हो गया है। उद्यमियों के मुताबिक, देश तो आजाद हो गया, लेकिन हम आज भी इस कानून के कारण मानसिक गुलामी झेल रहे हैं। जब तक जमीन फ्रीहोल्ड नहीं होगी, तब तक न तो उद्योग सुरक्षित महसूस करेंगे और न ही अगली पीढ़ी का भविष्य तय हो पाएगा।

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजेश कुमार यादव और महामंत्री गुलाब

» सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र में आज भी ब्रिटिश काल का लीज होल्ड कानून लागू

» उद्यमियों को मालिकाना हक नहीं, हर बदलाव के लिए अनुमति जरूरी

» अनुमति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप, बढ़ी परेशानी

» उद्योग विस्तार, निवेश और नवाचार पर सीधा असर

» फ्रीहोल्ड की मांग को लेकर उद्यमियों और महिलाओं का विरोध तेज

» आईआईए पदाधिकारियों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की

पाण्डेय सहित कई उद्यमियों ने सरकार से सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र की जमीन को फ्रीहोल्ड करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे उद्योगों को स्थायित्व मिलेगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इस मुद्दे पर महिलाओं ने भी खुलकर आवाज उठाई है।

स्वेता पाण्डेय और सुलेखा यादव सहित अन्य महिलाओं ने इसे औद्योगिक क्षेत्र के भविष्य के साथ अन्याय करार देते हुए कहा कि यह व्यवस्था परिवारों को असुरक्षा में धकेल रही है। स्पष्ट है कि सतहरिया में 'लीज होल्ड' कानून अब केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि



सुलेखा यादव



स्वेता पाण्डेय

औद्योगिक विकास की राह में सबसे बड़ा अवरोध बन चुका है। यदि समय रहते इस पर निर्णय नहीं लिया गया, तो यह क्षेत्र निवेश और विकास की दौड़ में और पीछे छूट सकता है।

सीएम युवा मिशन में जौनपुर अक्वल, स्वरोजगार की दौड़ में पूरे प्रदेश में बनाया कीर्तिमान

लक्ष्य से 151.56 प्रतिशत अधिक ऋण वितरण, हजारों युवाओं को मिला रोजगार का सहारा



» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

जौनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी सीएम युवा योजना प्रदेश के युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय होती जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत रिकॉर्ड आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे स्पष्ट है कि युवा स्वरोजगार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में जौनपुर जनपद ने पूरे प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है। जिले ने न केवल निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया बल्कि उससे कहीं अधिक ऋण वितरण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जौनपुर की यह उपलब्धि न केवल प्रशासनिक दक्षता

वया है सीएम युवा योजना

सीएम युवा योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें। यह योजना प्रदेश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सही दिशा और प्रयास से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना संभव है। प्रदेश स्तर पर इस योजना के तहत 1.5 लाख ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया था, जबकि कुल 3,86,092 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 3,30,441 आवेदन बैंकों को अग्रसारित किए गए, जिनमें 1,45,454 को स्वीकृति मिली और अब तक 1,38,304 युवाओं को ऋण वितरित किया जा चुका है।

जौनपुर जनपद की बात करें तो यहां 2,700 युवाओं को ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि 9,785 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 8,406 आवेदन बैंकों को भेजे गए और 4,092 युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण वितरित किया गया। इस प्रकार जिले ने लक्ष्य के सापेक्ष 151.56 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान का ही परिणाम है कि जौनपुर ने पूरे वर्ष प्रदेश में शीर्ष स्थान बनाए रखा। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप युवाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बैंकों के साथ समन्वय बनाकर तेजी से ऋण वितरण कराया जा रहा है।

उद्घाटन के 15 दिन में ही 'दम' तोड़ गया पीपा पुल, गुणवत्ता पर उठे सवाल

» हरसिंहपुर-विंध्याचल धाम को जोड़ने वाला पैटून पुल टूटने से आवागमन प्रभावित

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मिर्जापुर। जिले में विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। हरसिंहपुर और विंध्याचल धाम को जोड़ने के लिए बनाया गया पैटून (पीपा) पुल उद्घाटन के महज 15 दिन के भीतर ही क्षतिग्रस्त हो गया। इस पुल का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के विधायक रत्नाकर मिश्रा द्वारा किया गया था, जिसके बाद इसे क्षेत्रीय आवागमन के लिए खोला गया था।

आई जेनरेटेड प्रतीकात्मक फोटो



स्थानीय लोगों के अनुसार, पुल के कई हिस्सों में असंतुलन और ढांचे में ढीलापन दिखाई देने लगा है। कुछ जगहों पर पीपों के बीच का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे राहगीरों और वाहनों के लिए खतरा पैदा हो गया है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन आवागमन पर आंशिक रोक लगा दी है, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह पुल विशेष रूप से विंध्याचल धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग था। चैत्र नवरात्र जैसे धार्मिक आयोजनों के दौरान यहां

श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे में पुल का क्षतिग्रस्त होना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल के निर्माण में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई, जिसके कारण इतनी जल्दी यह स्थिति उत्पन्न हुई। लोगों ने निर्माण कार्य की जांच कराए जाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं, संबंधित विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गंगा नदी के जलस्तर और तेज बहाव के कारण पुल को नुकसान पहुंचा है। उनका दावा है कि मरम्मत कार्य जल्द शुरू कर पुल को फिर से सुरक्षित बनाया जाएगा।

छात्रा शैलजा गुप्ता ने एसडीएम को भेंट किया पेंसिल स्केच

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखीमपुर खीरी। रकेहटी गांव की छात्रा शैलजा गुप्ता ने अपनी कला से सभी को प्रभावित किया है। वह सजातक की पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं, वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। उसने एसडीएम निवासन राजीव निगम का पेंसिल से बेहद आकर्षक स्केच तैयार किया। खास बात यह है कि शैलजा ने बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के अपनी मेहनत और लगन से यह कला सीखी है। शैलजा स्वयं तहसील स्थित एसडीएम कार्यालय पहुंचीं और अपने हाथों से बनाया गया स्केच एसडीएम राजीव निगम को भेंट किया।



स्मार्ट मीटर का लगाने का अभियान तेज

बिजली विभाग का दावा, 1.02 लाख घरों में इंस्टॉलेशन पूरा

पारदर्शी बिलिंग और बेहतर निगरानी से उपभोक्ताओं को होगा लाभ

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। जनपद में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान तेजी पकड़ चुका है। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता बृजेंद्र कुमार ने बताया कि अयोध्या जनपद में कुल 5.03 लाख

उपभोक्ताओं में से अब तक 1 लाख 12 हजार घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। जल्द ही सभी पुराने मीटर बदलने का लक्ष्य है।

उन्होंने कहा कि पूरे मंडल के करीब 20 लाख उपभोक्ताओं को इस नई व्यवस्था से घबराने की जरूरत नहीं है। जिनके पास



कनेक्शन नहीं है वह नया लगवा का मीटर खुद बदल देगा। जिनका पुराना बकाया है वह उसे जमा

करके नया मीटर लगवा लें। स्मार्ट मीटर प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी और सटीक है। प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को समय से रिचार्ज कराना होगा, अन्यथा तीन दिन बाद कनेक्शन स्वतः कट जाएगा, जबकि पोस्टपेड में 30 दिन की मोहलत मिलती है। उनका कहना है कि पूरे अयोध्या जोन में 55 हजार 192 उपभोक्ताओं जिनका कुल बकाया लगभग 40 करोड़ था। उसमें से 13 मार्च से 28 मार्च तक अपने कुल बकाया भुगतान 28 करोड़ जमाकर स्मार्ट मीटर लगवा लिया है। बाकी उपभोक्ताओं से भी अपील है कि



अपने बकाया विद्युत बिल का भुगतान कर स्मार्ट मीटर लगवा ले इससे उन्हें बाकी सुविधायें मिलने लगेगी। मीटर तेज चलने की शिकायतों पर अधीक्षण अभियंता का कहना था कि हमने कुल उपभोक्ताओं के हिसाब से 5 प्रतिशत के यहाँ जांच मीटर लगवाया जिसकी जांच में रीडिंग समान पाई गई और बिल सही है। विभाग का दावा है कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को सटीक बिलिंग, खपत पर नियंत्रण और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगा।

उद्योगपति गौतम अडानी ने परिवार सहित किए रामलला के दर्शन



बोले, संस्कृति और आत्मविश्वास का प्रतीक है मंदिर

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी गुरुवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद वे लखनऊ के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि परिवार सहित रामलला के दर्शन का अवसर मिलना उनके लिए अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति और आत्मविश्वास का

प्रतीक है। प्रभु श्री राम के आदर्श सत्य, सेवा और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने देश की निरंतर प्रगति के लिए भगवान से आशीर्वाद की कामना की। दर्शन के उपरांत गौतम अडानी ने एक गुरुकुल में भी पहुंचकर बच्चों के साथ समय बिताया। उन्होंने कहा कि गुरुकुल भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अडानी फाउंडेशन की ओर से गुरुकुलों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया गया।

हनुमान जयंती पर रामनगरी में लहराया भगवा ध्वज

34 साल बाद दिखा ऐतिहासिक संगम, पूरा परिसर जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती के अवसर पर रामनगरी भक्ति और उल्लास में डूबी नजर आई। श्रीराम जन्मभूमि परिसर स्थित हनुमान मंदिर के शिखर पर विधि-विधान से भगवा ध्वज फहराया गया। जैसे ही ध्वज लहराया, पूरा परिसर जय श्रीराम और जय बजरंगबली के जयघोष से गूंज उठा। ध्वजारोहण कार्यक्रम में बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार के साथ जयभान सिंह पवैया, प्रकाश शर्मा और सुरेंद्र जैन ने संयुक्त रूप से भाग लिया। करीब 34 वर्षों बाद ऐसा अवसर आया जब संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी एक साथ मंदिर परिसर में जुटे। धार्मिक अनुष्ठान के दौरान साधु-संतों की उपस्थिति ने माहौल को और अधिक भावुक बना दिया। कई संतों की आंखें नम दिखीं। लगभग 200 विशिष्ट अतिथियों ने इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बने।



भारतीय संस्कृति का यशगान हो रहा: विनय कटियार

ध्वजारोहण के बाद विनय कटियार ने कहा कि यह आयोजन भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा का प्रतीक है। ऐसे आयोजन सांस्कृतिक चेतना को सशक्त करते हैं।

आईएमए अध्यक्ष की मौजूदगी में कैंसर उपचार पर संगोष्ठी



» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। सिनर्जी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल एवं कैंसर संस्थान द्वारा अयोध्या चिकित्सक संघ के सहयोग से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का

मुख्य विषय कैंसर के समग्र उपचार पर आधारित रहा, जिसमें आधुनिक उपचार तकनीकों और बचाव के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम में चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉ. आशीष श्रीवास्तव और सचिव डॉ. निशांक सक्सेना उपस्थित

रहे। उन्होंने ऐसे शैक्षणिक आयोजनों को चिकित्सा क्षेत्र के लिए उपयोगी बताया। अस्पताल की ओर से डॉ. आलोक तिवारी, डॉ. सौरभ मिश्रा, डॉ. अंजलि जैन और डॉ. सी. पी. अवस्थी ने कैंसर उपचार की नई विधियों और

बेहतर परिणामों पर विचार साझा किए। विशेषज्ञों ने कैंसर की समय पर पहचान, रोकथाम और उचित उपचार पर बल देते हुए जन-जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ चिकित्सक भी मौजूद रहे।

ईरान के 400 किलो यूरेनियम पर 'अमेरिकी नजर'

60% एनरिच स्टॉक पर 'सीधा एक्शन' का प्लान, मलबे में दबे परमाणु भंडार तक पहुंचने के लिए महीनों का ऑपरेशन, हजारों सैनिक और हाई-रिस्क मिशन की आशंका

स्वराज इंडिया न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एक नई और बेहद खतरनाक रणनीतिक चर्चा सामने आई है, जिसने वैश्विक सुरक्षा ढांचे को हिला दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से जुड़े रणनीतिक हलकों में ईरान के संवेदनशील परमाणु भंडार खासतौर पर 400 किलोग्राम से अधिक उच्च संवर्धित यूरेनियम को सैन्य कार्रवाई के जरिए अपने नियंत्रण में लेने की संभावना पर गंभीर विचार चल रहा है। हालांकि इस योजना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और सुरक्षा एजेंसियों में गहरी चिंता पैदा कर दी है।

सूत्रों के अनुसार, ईरान के पास इस समय करीब 440 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है, जिसे 60 प्रतिशत तक एनरिच किया जा चुका है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रीसी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यह मात्रा सैद्धांतिक रूप से 10 से अधिक परमाणु बम बनाने की क्षमता रखती है, भले ही हथियार-स्तर के लिए 90 प्रतिशत एनरिचमेंट आवश्यक हो। बताया जा रहा है कि यह यूरेनियम इस्फाहान और नतांज जैसे परमाणु ठिकानों पर मौजूद है, जिनमें हालिया हमलों के बाद भारी क्षति हुई है। इन ठिकानों के ढांचे का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है, जिससे यूरेनियम तक पहुंचना और भी जटिल हो गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर अमेरिका इस यूरेनियम को हासिल करने का प्रयास करता है, तो यह किसी भी हालिया सैन्य मिशन से कहीं अधिक जटिल और जोखिमपूर्ण होगा। मलबे में दबे रेडियोधर्मी पदार्थ को सुरक्षित निकालने के लिए न केवल अत्याधुनिक तकनीक बल्कि विशेष परमाणु विशेषज्ञों और हजारों सैनिकों की जरूरत होगी। महीनों का ऑपरेशन, वैश्विक जोखिम



होर्मुज संकट से दुनिया बेहाल

ईरान से जुड़े इस तनाव का असर केवल परमाणु खतरे तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था भी इसकी चपेट में है। होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से तेल आपूर्ति की सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइन बाधित हो गई है। 'फाइनेंशियल टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, अब दुनिया भर के देश वैकल्पिक ऊर्जा मार्गों की तलाश में जुट गए हैं। पाइपलाइन, रेलवे और सड़क मार्ग के जरिए तेल परिवहन के विकल्पों पर तेजी से काम हो रहा है। खाड़ी देशों के लिए यह संकट एक बड़ा झटका साबित हुआ है। हालांकि सऊदी अरब ने पहले से ही लाल सागर तक पाइपलाइन नेटवर्क तैयार कर रखा था, जिससे उसकी ऊर्जा आपूर्ति पर अपेक्षाकृत कम असर पड़ा है।

इस पूरे ऑपरेशन में महीनों का समय लग सकता है। अस्थायी रनवे तैयार कर भारी-भरकम कार्यों विमानों की मदद से यूरेनियम को बाहर ले जाने की योजना पर भी विचार हो सकता है। इस दौरान रेडिएशन रिसाव, स्थानीय विरोध और ईरानी सैन्य प्रतिक्रिया जैसे कई बड़े खतरे मौजूद रहेंगे। इतिहास में

एआई जेनरेटेड प्रतीकात्मक फोटो

ईरान परमाणु संकट: रणनीतिक प्रभाव



भारत के लिए नया मौका या चुनौती?

इस संकट के बीच इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकॉनॉमिक कॉरिडोर एक बड़े रणनीतिक विकल्प के रूप में उभर रहा है। इस कॉरिडोर के जरिए भारत, मध्य एशिया और यूरोप के बीच एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी नेटवर्क विकसित किया जा सकता है। इसमें यू.ए.ई., सऊदी अरब, जॉर्डन और इजरायल को जोड़ते हुए पाइपलाइन, रेलवे और सड़क नेटवर्क शामिल होगा। हाइफा पोर्ट के माध्यम से अरब सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने की योजना पर भी तेजी से चर्चा हो रही है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जमीन पर उतरने में समय लगेगा, लेकिन दीर्घकाल में यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा का नया आधार बन सकता है। हालांकि यह पूरा घटनाक्रम अभी रणनीतिक और खुफिया चर्चाओं के स्तर पर है, लेकिन इसके संभावित असर इतने व्यापक हैं कि दुनिया की नजरें अब पश्चिम एशिया पर टिकी हैं।

अमेरिका ने 1994 में 'प्रोजेक्ट सफायर' के तहत कजाकिस्तान से वेपन-ग्रेड यूरेनियम

क्या सच में 'तुरंत परमाणु खतरा'?

60% एनरिचमेंट को लेकर डर जरूर है, लेकिन यह अभी हथियार-स्तर (90%) से नीचे है। हालांकि तकनीकी रूप से इसे आगे बढ़ाना ज्यादा कठिन नहीं होता, इसलिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां इसे 'रेड अलर्ट' मानती हैं।

अमेरिका के लिए कितना जोरिबम?

ईरान के भीतर जाकर यूरेनियम निकालना सीधा सैन्य टकराव को न्योता दे सकता है। यह मिशन केवल तकनीकी नहीं, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक विस्फोट भी साबित हो सकता है।

तेल संकट से कौन जीतेगा?

होर्मुज संकट ने यह साफ कर दिया कि जिन देशों के पास वैकल्पिक रूट हैं जैसे सऊदी वे इस संकट में भी मजबूत स्थिति में रहेंगे, जबकि बाकी दुनिया अस्थिरता झेलेगी।

भारत के लिए 'गेम चेंजर' मौका?

आईएमईसी कॉरिडोर भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में नई ताकत दे सकता है। अगर यह प्रोजेक्ट समय पर लागू होता है, तो भारत ऊर्जा और व्यापार दोनों में रणनीतिक बढ़त हासिल कर सकता है।

सुरक्षित निकाला था, लेकिन मौजूदा हालात उससे कहीं अधिक संवेदनशील और विस्फोटक माने जा रहे हैं।

यूपी के 1.37 लाख शिक्षकों को स्वास्थ्य कवच, अब 5 लाख तक कैशलेस इलाज

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उनके लिए व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू की है। इस फैसले के तहत प्रदेश के विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) डिग्री कॉलेजों और स्वचिन्तपोषित (सेल्फ-फाइनेंस) महाविद्यालयों में कार्यरत करीब 1.37 लाख शिक्षकों को अब कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शिक्षक और उनके परिवार के सदस्य एक वर्ष में अधिकतम पांच लाख रुपये तक का मुफ्त उपचार करा सकेंगे। यह सुविधा

सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में भी सुविधा, परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा लाभ

सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ पैन्ल में शामिल निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी, जिससे इलाज के विकल्प बढ़ेंगे और बेहतर चिकित्सा सेवाएं सुलभ हो सकेंगी।

इस योजना की सबसे खास बात इसका व्यापक दायरा है। इसमें न केवल नियमित शिक्षक बल्कि स्वचिन्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षक और मान्यता प्राप्त निजी डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में गैर-नियमित शिक्षकों को भी सरकारी स्वास्थ्य



सुविधा का लाभ मिलेगा, जो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे।

नई व्यवस्था से शिक्षकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान आर्थिक दबाव

से राहत मिलेगी। अब उन्हें इलाज के लिए कर्ज लेने या अपनी बचत पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैशलेस सुविधा के कारण अस्पतालों में सीधे उपचार संभव होगा, जिससे समय और प्रक्रिया दोनों में आसानी आएगी।

सरकार के इस निर्णय का शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह कदम न केवल शिक्षकों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में कार्यरत कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इस योजना से उच्च शिक्षा क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन आएगा तथा शिक्षकों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा।

